अमेरिका-भारत व्यापार

अनिश्चित दौर में भी निश्चित

लॉरिंडा कीज़ लौंग

इयान वुकर्स © ए.पी.-डब्ल्यू.डब्ल्यू.पी.

बन्द होते बैंक, कर्मचारियों की छंटनी और आर्थिक मंदी भी बढ़ते भारत-अमेरिकी व्यवसाय सम्बन्धों को रोकने के लिए काफी नहीं हैं। भविष्य में और भी वृद्धि और सहयोग के विश्वास से भरी यू.एस.-इंडिया बिज़नेस काउंसिल ने हाल ही में भारत में अपने पहले स्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया। न्यू यॉर्क सिटी ट्रेवल एंड टूरिज़्म ब्यूरो ने भी हाल ही में भारत में अपना पहला स्थायी कार्यालय खोला और उधर हाल ही में पेप्सिको ने भी भारत में 50 करोड़ डालर की राशि भारत में निवेश के लिए नियत की है। अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता और भारत के पहले चन्द्र अभियान में नासा के सहयोग से व्यवसायी समुदाय में और भी साझा सौदों, व्यापार, प्रौद्यौगिकी हस्तांतरण और निवेश की सम्भावनाओं को लेकर आशा जागी है।

दोनों देशों के बीच वृद्धि को प्रेरित करने वाले 33 वर्षीय संगठन यू.एस.-इंडिया बिज़नेस काउंसिल ने तय किया कि नई दिल्ली में अपना पहला स्थायी कार्यालय स्थापित करने के लिए 24 सितम्बर एकदम सही समय है। कार्यालय फुलब्राइट हाउस में है जहां हाल ही में नया नाम पाने वाले 60 वर्षीय यू.एस.-इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन (यू.एस.आई.ई.एफ.) भी स्थित है- लगता है भारतीय और अमेरिकी व्यवसाय जगतों के शीर्षस्थ अगुआ जानते हैं कि भविष्य की दिशा क्या है।

भारत में जन्मी पेप्सिको की प्रमुख और यू.एस.-इंडिया बिज़नेस काउंसिल की चेयरमैन इन्द्रा के. नूयी के साथ कार्यालय का उद्घाटन करते हुए अमेरिकी डिप्टी चीफ़ ऑफ़ मिशन स्टीवन जे. व्हाइट ने कहा, ''जहां यू.एस.- इंडिया बिज़नेस काउंसिल व्यवसाय सम्बन्धों को मज़बूत बना रही है, वहीं यू.एस.-इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में सम्बन्धों को मज़बूत बना रही है। ये उद्देश्य एक-दूसरे को मज़बूत बनाते हैं और इन दो महान संगठनों के एक ही जगह स्थित होने से भारत में अपना प्रभाव छोड़ने की उनकी सामर्थ्य और भी बढ़ेगी।''

उन्होंने कहा, ''अमेरिका और भारत दोनों ही हमारे देशों के हितों को आगे बढ़ाने और विकास में व्यवसाय और शिक्षा की साझेदारी के महत्व से सुपरिचित हैं। आज हम यू.एस.-इंडिया बिज़नेस काउंसिल के जिस कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, वह अमेरिका के साथ भारत के सम्बन्धों की व्यापकता का प्रतीक है। और हमें पूरा विश्वास है कि यू.एस.-इंडिया बिज़नेस काउंसिल और यू.एस.-इंडिया एजुकेशनल

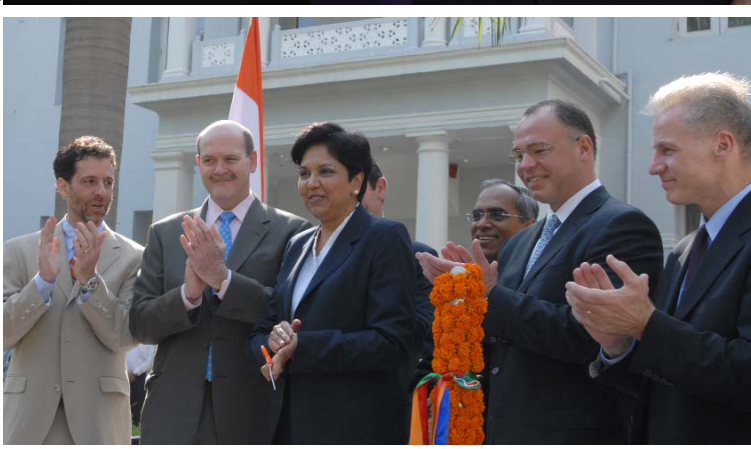

अर्ता मिश्रा

ऊपर: (बाएं से) सितंबर में अमेरिका-भारत व्यापार परिषद के दिल्ली कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर यू.एस.-इंडिया एजुकेशनल फ़ाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक एडम ग्रॉट्स्की, अमेरिका के डिप्टी चीफ़ ऑफ़ मिशन स्टीवन जे. व्हाइट, भारत-अमेरिका व्यापार परिषद की चेयरमैन इंद्रा के. नूयी, कोग्निज़ेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मी नारायणन, बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट इयान थॉमस और अमेरिका-भारत व्यापार परिषद के प्रेसिडेंट रॉन समर्स।

> "अनिश्चितता की इस पृष्ठभूमि के बावजूद दूरदर्शी अमेरिकी व्यवसाय और उन लाखों भारतीयों के लिए भारतीय विकास की दास्तां में ज़बर्दस्त संभावना है जो प्रतिदिन समृद्धि, विकास और प्रगति के और नए अवसर देख पाते हैं।"
>
> -अमेरिकी डिप्टी चीफ़ ऑफ़ मिशन स्टीवन जे. व्हाइट, 23 सितंबर को नई दिल्ली में।

बिल्कुल ऊपर बाएं: नवंबर में वित्तीय बाज़ारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर आयोजित सम्मेलन में वाशिंगटन, डी.सी. में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश।

फाउंडेशन का एक ही जगह स्थित होना इस सम्बन्ध को और प्रगाढ़ बनाएगा।''

नूयी केवल फीता काटने और ''भारत के साथ एक मज़बूत साझेदारी के प्रति यू.एस.-इंडिया बिज़नेस काउंसिल की प्रतिबद्धता को स्थापित'' करने ही नहीं आई थीं। उन्होंने दोहराया कि ''पेप्सिको भारत के प्रति प्रतिबद्धता वाली वैश्विक कम्पनी है'' और वह भारत की कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और ''खेत से मंडी तक की आपूर्ति शृंखला'' को और तेज़ करने के तरीके तलाशने आए एक यू.एस.-इंडिया बिज़नेस काउंसिल कार्यकारी मंडल का नेतृत्व कर रही है।

अपनी वेबसाइट www.usibc.com पर अपना परिचय देते हुए संगठन बताता है कि उसकी स्थापना वर्ष 1975 में यू.एस. चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के तहत हुई थी। यह ''भारत में निवेश कर रही 300 सबसे बड़ी अमेरिकी कम्पनियों और दो दर्ज़न ऐसी वैश्विक भारतीय कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रमुख व्यवसाय पक्षनिर्माण संगठन है, जिनका लक्ष्य व्यापार को बढ़ाना और अमेरिका-भारत वाणिज्य सम्बन्धों को मज़बूत करना है।''

वर्ष 2004-05 में आज के यू.एस.-इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन के बोर्ड के सदस्य रह चुके यू.एस.-इंडिया बिज़नेस काउंसिल के प्रेसिडेंट रॉन सॉमर्स ने कहा कि जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग पहल को अंतिम रूप देकर ''भारत के विरुद्ध लागू की गई प्रौद्योगिकी देने पर रोक की व्यवस्था का अंत करने'' वाशिंगटन डी.सी. पहुंच रहे हैं, उसी समय काउंसिल का भारत में अपनी स्थायी उपस्थिति दर्ज़ कराना एक शुभ संकेत है। ''इससे बनने वाली सहयोग की भावना आगामी कई पीढ़ियों तक हमारे देशों के लोगों के बीच सम्बन्धों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी और 21वीं सदी की आर्थिक नियति को आकार देने में सहायता करेगी।''

भारत के असैन्य रिएक्टरों के अंतरराष्ट्रीय निरीक्षणों के बदले भारत को परमाणु ईंधन दिए जाने की अनुमति देकर अमेरिकी-भारत असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते ने तीन दशक से अधिक की अमेरिकी नीति को उलट दिया है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा दोनों बड़े राजनीतिक दलों के सहयोग से पारित विधेयक भारत को 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद से पहली बार अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की अनुमति देता है।

अक्टूबर में विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने कहा, ''विधेयक परमाणु अप्रसार के हमारे वैश्विक प्रयासों को मज़बूत बनाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, नौकरियों का सृजन करेगा और अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से पूर्ति करने में भारत की सहायता करेगा। ''

नवंबर में अमेरिकी राजदूत डेविड सी. मल्फ़र्ड ने कन्फेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री को बताया, ''मैं उत्साहपूर्वक कहता हूं कि अमेरिकी कम्पनियों की, सही स्थितियों में, भारत के साथ वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा उद्योग में भागीदारी और व्यवसाय करने में रुचि है।'' राजदूत ने कहा कि परमाणु सौदा बहुत संतोषजनक और ऐतिहासिक उपलब्धि है लेकिन, ''भारत में एक बड़ा, विश्वस्तरीय, असैन्य परमाणु उद्योग खड़ा करने में समय, पूंजी, प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकी, एक बढ़िया विनियामक ढांचे, निजी क्षेत्र के निवेश और श्रेष्ठता के प्रति वास्तविक राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पड़ेगी।''

उन्होंने कहा, ''एक अकुशल विद्युत प्रणाली के लिए बिजली उत्पादित करने वाले थोड़े से और छोटे रिएक्टरों से भारत को वांछित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। भारत को एक ऐसी सार्वजनिक-निजी असैन्य परमाणु रणनीति चाहिए जो बड़े पैमाने पर और प्रतिस्पर्धी विद्युत उत्पादन के लिए सक्षम, पारदर्शी नीतियों की स्थापना करे। मैं आशा करता हूं कि भारत एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय असैन्य परमाणु उद्योग का जन्म स्थान बन पाएगा लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति एक बड़ी चुनौती है।''

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आधारभूत ढांचा विकास, साझा व्यापार अवसरों और अंततः भारत के व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की लागतें कम करने के अवसर तैयार करने वाला असैन्य परमाणु सहयोग समझौता आर्थिक अनिश्चितता और वित्तीय अस्थिरता के घिरते बादलों के बीच आशा की एक किरण है।

पुरानी कहावत है कि दुनिया का कारखाना तो हर हाल में चलता रहता है। यस बैंक में बिज़नैस बैंकिंग के ग्रुप प्रेज़िडेंट वरुण तुली इससे पूरी तरह सहमत हैं। फुलब्राइट हाउस में यू.एस.-इंडिया बिज़नेस काउंसिल के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में मौजूद तुली ने कहा, ''हां, व्यापार तो चलता ही रहेगा। बहुत सी नई संभावनाएं उभर रही हैं।'' इन उभरती संभावनाओं में से कुछ हैं- जल्दी ही भारत आ रहा यू.एस.कमर्शियल न्यूक्लिर मिशन, जनवरी के अंत में यू.एस.सोलर एनर्जी मिशन और फ़रवरी के अंत में केंटकी राज्य का नैशविल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स मिशन।

भारत-अमेरिका सम्बन्धों में एक और प्रतीकात्मक और व्यवहार्य कदम था अक्टूबर में मुंबई में न्यू यॉर्क सिटी के पर्यटक और यात्रा प्रोत्साहन खंड के भारत कार्यालय का खुलना। न्यू यॉर्क सिटी एंड कम्पनी के सी.ई.ओ. जॉर्ज फेर्तिता ने कहा कि पिछले बरस करीब 150,000 भारतीय न्यू यॉर्क आए। भारत स्थित कार्यालय का उद्देश्य भविष्य में और अधिक लोगों को न्यू यॉर्क आने को प्रेरित करना और उनके लिए यात्रा को आसान बनाना है। यह कार्य वेबसाइट nycvisit.com पर भारतीय यात्रियों और ट्रेवल एजेंटो के लिए प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी किया जाएगा। नई दिल्ली में एक समारोह में फेर्तिता ने कहा, ''हम फिर यहां आएंगे और इस बारे में खूब बातें करेंगे कि यह कितने कमाल का देश है, और हमें आशा है कि आप भी हमारे यहां आएंगे और हमारे गज़ब के शहर के बारे में बातें करेंगे।''

हाल की आर्थिक मंदी में अमेरिका और भारत के बीच पर्यटन में 10 प्रतिशत की कमी आने के बावजूद यह दीर्घावधि में एक स्थिर व्यवसाय है क्योंकि अमेरिका में भारतीय मूल के 35 लाख लोग हैं। एसटीआइसी ट्रेवल ग्रुप के अध्यक्ष सुभाष गोयल कहते हैं, ''जो भी हो ये लोग यात्रा करेंगे ही। साल में एक बार नहीं तो तीन या पांच साल में एक बार तो वे अपने मित्रों और परिवार से मिलने, पारिवारिक समारोहों या अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए भारत आएंगे न। पर्यटकों की आवाजाही कम होने के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच यात्राएं कम होती नहीं दिखतीं।''

सुभाष गोयल को जिस बात से आशा बंधती है वह है, ''आर्थिक संकट के दौरान लोग लागत में कमी के बारे में सोचते हैं। फिर वह उन क्षेत्रों और जगहों के बारे में

अमेरिकी असैन्य परमाणु ऊर्जा के कुछ तथ्य

- अमेरिका संसार में बिजली का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से 20 प्रतिशत परमाणु ऊर्जा द्वारा उपलब्ध होती है।
- परमाणु बिजली उत्पादन क्षमता (100,582 मेगावाट) के मामले में अमेरिका संसार में पहले स्थान पर है। यह संसार में उत्पादित हो रही कुल परमाणु ऊर्जा का 27 प्रतिशत है।
- संसार में सबसे अधिक परमाणु रिएक्टर, 104 अमेरिका में हैं जो संसार के परमाणु रिएक्टरों का 24 प्रतिशत हैं।
- अन्य बड़े देशों की तुलना में अमेरिका में परमाणु ऊर्जा की उत्पादन लागत आधी या तिहाई ही है।
- पिछले 15 सालों में अमेरिकी असैन्य परमाणु इंजीनियरिंग कम्पनियां वैश्विक स्तर पर इस उद्योग में अग्रणी हैं। निरन्तर आधुनिकीकरण और बेहतरी करते हुए वे अमेरिकी उद्योग को संसार का सबसे कुशल और प्रतिस्पर्धात्मक उद्योग बनाए हुए हैं।

-अमेरिकी राजदूत डेविड सी. मल्फ़र्ड 14 नवंबर, नई दिल्ली।

ज़्यादा जानकारी के लिए:

अमेरिका-भारत व्यापार परिषद

http://www.usibc.com/usibc/default

भारतीय उद्योग परिसंघ

http://www.ciionline.org/full_story.php?menu_id=79&news_id=1909

सोचते हैं जहां वही काम कम लागत पर हो सकता है। इसका परिणाम यह होगा कि भारत से और भी आउटसोर्सिंग होगी। बहुत सी आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर चल रहा काम भी एक सकारात्मक संकेत है। पहले चरण में 14 हवाई अड्डों का स्तर सुधारा जा रहा है, दूसरे दर्ज़े के शहरों में करीब 50 हवाई अड्डों का स्तर सुधारा जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि उड्डयन, इंजनों, एक्स-रे मशीनों, लैंडिंग उपकरणों के क्षेत्र में विश्व शक्ति अमेरिका को भारत से व्यापार करने के बहुत से अवसर मिलेंगे।''

व्यापारी समुदाय की आशाभरी दृष्टि चंद्रयान-1 चंद्र अभियान पर भी टिकी है जो चंद्रमा के संसाधनों के अन्वेषण के उद्देश्य से भारतीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों की सहयोगी परियोजना है। 21 अक्टूबर को रॉन सॉमर्स और अमेरिकी उद्योग जगत के 100 से भी अधिक शक्तिशाली प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन डी.सी. में इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण का लाइव वीडियो फीड देखा। सॉमर्स कहते हैं, ''हम आशा करते हैं कि असैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण में यह अनूठी प्रौद्योगिकी साझेदारी जिसमें भारत की अत्यन्त दक्ष वैज्ञानिक विशेषज्ञता और रेथियॅन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अमेरिकी उपकरणों का उपयोग किया गया है, अंतरिक्ष की सीमाओं के द्वार खोलने को प्रोत्साहित करने वाले एक लम्बे और परस्पर लाभकारी सम्बन्ध की शुरुआत होगी।''